



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]
No. 178]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2000/चैत्र 2, 1922
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2000/CHAITRA 2, 1922

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2000

का.आ. 261(अ).—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन साउथ इंडिया कॉटन एसोसिएशन, कोयम्बटूर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसिएशन को रूई में अग्रिम संविदा (अनंतरणीय विनिर्दिष्ट) के बारे में 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2002 तक के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा मान्यता इस शर्त के अध्वधीन दी जाती है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएंगे।

[मिसिल सं. 12/1/आईटी/98]

कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC
DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2000

S.O. 261(E).— The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the South India Cotton Association, Coimbatore, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in public interest so to do, hereby grants in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period from 1st April, 2000 to 31st March, 2002 in respect of forward contracts (N.T.S.D.) in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12/1/IT/98]

KAMAL KISHORE, Economic Adviser